करेंट अफेयर्स झारखंड

अगस्त 2021

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

झारखंड **5**

- झारखंड मोटरवाहन (संशोधन) नियमावली, 2021 5
- स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (School of Excellence) 5
- खरसावाँ हल्दी 'इनोवेटिव प्रोडक्ट आईडियाज' के लिये चयनित 6
- व्यवहार विज्ञान पर समझौता ज्ञापन 6
- आदिवासियों के लिये सैटेलाइट चैनल 6
- KCC एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम 7
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (Birsa Agricultural University) 7
- राज्य के नेत्र रोग विशेषज्ञों का 'कोविड वारियर्स'के रूप में सम्मान 7
- "बीसी सखी" पहल ("BC Sakhi" initiative) 8
- दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने बांग्लादेश को भेजी सातवीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 8

नोट :

- गोड्डा में 60 योजनाओं का शिलान्यास 9
- टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तीसरा फुट ओवरब्रिज 9
- लाभार्थियों को नियुक्ति-पत्र व प्रमाण-पत्र का वितरण 10
- सौर ऊर्जा से संचालित होंगे राज्य के पाँच हवाई अड्डे 10
- फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 10
- मेधा कृषि उत्सव 11

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

झारखंड

झारखंड मोटरवाहन (संशोधन) नियमावली, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 27 जुलाई, 2021 को झारखंड कैबिनेट ने झारखंड मोटरवाहन (संशोधन) नियमावली, 2021 को मंज़ूरी प्रदान कर दी है, जिसमें आवेदन शुल्क, लाइसेंस शुल्क व परमिट शुल्क में दोगुनी वृद्धि की गई है।

प्रमुख बिंदु

- लर्निंग लाइसेंस जाँच शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।
- सवारी गाड़ियों, यात्री बसों तथा मोटर कैब के परमिट शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है।
- पर्यटक वाहनों के लिये शुल्क में बढ़ोतरी करके इसकी राशि को 1500 रुपए कर दिया गया है।

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (School of Excellence)

चर्चा में क्यों ?

- 31 जुलाई, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूलों को 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' में परिवर्तित कर राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री के विज़न के अनुसार लगभग पाँच हज़ार सरकारी स्कूलों को क्रमवार आधुनिक शिक्षा सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसका प्रारंभिक उद्देश्य 2022-23 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत तक 80 ज़िलास्तर के उत्कृष्ट स्कूलों के लगभग दो लाख छात्रों को लाभ पहुँचाना है।
- सरकार का लक्ष्य सत्र 2022-23 शुरू होने से पहले 80 ज़िलास्तरीय उत्कृष्ट स्कूलों, 2023-24 के सत्र से पहले 329 ब्लॉक स्कूलों और 2024-25 के सत्र से पहले 4,000 से अधिक पंचायत स्तर के स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाना है।
- पहले चरण में राज्य के सभी ज़िलों के प्रस्तावित 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्ट स्कूल) में तब्दील किया जा रहा है।
- इन स्कूलों का विकास निजी स्कूलों के मॉडल पर किया जा रहा है। ये सभी 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली से आच्छादित रहेंगे और निर्बाध बिज़ली आपूर्ति, स्वच्छ वातावरण और स्मार्ट बोर्ड जैसी अन्य सुविधाओं से सुसज्जित होंगे।
- पूर्व में स्कूलों में साफ-सफाई और शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर अधिक थी, जिसे दूर करने के लिये सरकार ने सभी स्कूल परिसरों को लड़कियों और लड़कों दोनों के लिये अलग-अलग शौचालय सुविधा बहाल करने करने की योजना बनाई है।
- इन मॉडल स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार के लिये एक समर्पित भाषा प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और इसका उपयोग समीक्षा तंत्र उपकरण के रूप में भी किया जाएगा।
- देश के प्रमुख संस्थानों की मदद से 'उत्कृष्ट स्कूल' में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्री-प्राइमरी स्तर से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस योजना से राज्यभर के लगभग 15 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।

नोट :

खरसावाँ हल्दी 'इनोवेटिव प्रोडक्ट आईडियाज' के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड के सरायकेला खरसावाँ ज़िले की ऑर्गेनिक हल्दी को 'अवॉर्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज' के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली में आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस हल्दी के लिये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
- इसके अलावा बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, नगालैंड, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र के उत्पाद भी पुरस्कार हेतु चयनित किये गए हैं।
- राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला द्वारा खरसावाँ हल्दी के पाउडर को जाँच करने पर 7.01 प्रतिशत करक्यूमिन पाया गया, जो सामान्य हल्दी में केवल 2 प्रतिशत होता है।
  - करक्यूमिन हल्दी में मौजूद विशेष गुणों का मापक है।
- इसका इस्तेमाल त्वचा संबंधी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है तथा यह शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने के साथ-साथ कैंसर एवं हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज हेतु भी उपयोगी है।

व्यवहार विज्ञान पर समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

- 08 अगस्त, 2021 को जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (XISS), राँची और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री (CIP), राँची ने शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, संयुक्त परियोजनाओं, इंटर्नशिप, FDP, अतिथि व्याख्यान आदि के क्षेत्र में सहयोग करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौते पर XISS के निदेशक एस.जे. कुजुर और CIP के निदेशक प्रो. वासुदेव दास ने हस्ताक्षर किये।
- इस समझौते के तहत सेंटर ऑफ बिहेवेरियल एंड कॉग्निटिव साइंसेज (सीबीसीएस), एक्सआईएसएस (XISS) और सीआईपी (CIP) समुदाय और परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के अलावा व्यवहार विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायकि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त सहयोगी अनुसंधान परियोनाओं और कार्यक्रमों का आयोजन और विकास करेंगे।
- इस साझेदारी के तहत, XISS और CIP संस्थान के नवोदित स्नातकों के तकनीकी उन्नति, नवाचार और उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के कौशल का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

आदिवासियों के लिये सैटेलाइट चैनल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय के लिये उनकी अपनी भाषा का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल 'ट्राइब टीवी' लॉन्च किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह चैनल संथाली भाषा में प्रसारित होगा। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में इस चैनल का मुख्यालय होगा तथा कल्याणी सोल्वेक्स नामक संस्था इसका संचालन करेगी।
- उल्लेखनीय है कि संथाली भारतीय संविधान में अधिसूचित 22 भाषाओं में से एक है।

नोट :

- संथाली के बाद ट्राइब टीवी की योजना अन्य लोकप्रिय जनजातीय भाषाओं, जैसे- मुंडारी, कुड़ुख आदि में भी लॉन्च की जाएगी।
- ट्राइब टीवी का केंद्रबिंदु, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल आदि राज्यों पर होगा।

KCC एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

- 9 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा के सम्मान में लगभग 2 लाख कृषकों को KCC एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम के तहत कुल 734 करोड़ रुपए वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री द्वारा 'विश्व आदिवासी दिवस' के अवसर पर बिरसा मुंडा एवं अन्य जनजाति नेताओं को सम्मान देते हुए कृषकों को यह धनराशि वितरित की गई।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कृषकों की आय में वृद्धि करके राज्य में गरीबी को कम करना है। साथ ही पशुधन वितरण से राज्य में उपस्थित कुपोषण की समस्या का भी समाधान करना है।
- इस अवसर पर झारखंड में कृषकों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करके राज्य के जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान को बढ़ाए जाने की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त की गई।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (Birsa Agricultural University)

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ग्यारह उच्च उपज, जल्दी परिपक्व और रोग-कीट प्रतिरोधी फसल किस्में जारी की गईं।

प्रमुख बिंदु

- इन किस्मों को कृषि सचिव, अबुबकर सिद्दीकी की अध्यक्षता में राज्य किस्म विमोचन समिति द्वारा गहन चर्चा और प्रश्नों के अनुपालन के बाद जारी किया गया था।
- इन किस्मों में एक-एक काला चना, अरहर, सोयाबीन, सरसों, बेबी कॉर्न, रागी, दो बैंगन और तीन अलसी शामिल हैं। मौजूदा पारंपरिक किस्मों की तुलना में इन किस्मों की उपज लाभ 15 से 20 प्रतिशत है।
- बीएयू के कुलपति, डॉ. ओंकार नाथ सिंह और निदेशक अनुसंधान, डॉ. ए. वदूद ने बताया कि इन किस्मों से दालों, तिलहनों और सब्जियों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- बीएयू फसल प्रजनक, बीज और फार्म निदेशालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य के बीज गाँव किसानों को इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिये इन फसलों के बीज उत्पादन हेतु आपस में सहयोग करेंगे।

राज्य के नेत्र रोग विशेषज्ञों का 'कोविड वारियर्स'के रूप में सम्मान

चर्चा में क्यों ?

- 11 अगस्त, 2021 को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के 45 नेत्र रोग विशेषज्ञों को महामारी के दौरान कोविड रोगियों और उनके परिवारों की मदद करने के उनके अथक् प्रयासों के लिये 'कोविड वारियर्स'के रूप में सम्मानित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राँची में झारखंड नेत्र रोग सोसायटी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने नेत्र रोग विशेषज्ञों को यह सम्मान प्रदान किया।
- इन नेत्र रोग विशेषज्ञों ने अपने आराम क्षेत्र को छोड़कर, पेशेवर सीमाओं को पार करते हुए अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों को कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने के लिये सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित की थी।
- सम्मान समारोह में डॉ. विभूति कश्यप को 'डॉ. वी.एस. गुप्ता बेस्ट फ्री पेपर' और डॉ. राहुल प्रसाद को 'मंजुल पंत बेस्ट वीडियो सेशन' के लिये गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। डॉ. ललित जैन को उनके एक्स्ट्राम्यूरल ओरेशन के लिये सम्मानित किया गया।
- स्वास्थ्य मंत्री ने महामारी में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए डॉक्टरों के परिजनों को शॉल और स्मृति चिह्न भी भेंट किये। कोरोना महामारी के शिकार हुए राज्य के प्रख्यात चिकित्सक डॉ. कृष्ण मुरारी साहू, डॉ. सुजीत कुमार पॉल और डॉ. चंद्रिका किशोर ठाकुर के परिवारों का अभिनंदन भी किया गया।

"बीसी सखी" पहल ("BC Sakhi" initiative)

चर्चा में क्यों ?

- 12 अगस्त, 2021 को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ बैंकिंग संवाददाता के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु 'बीसी सखी पहल' का ऑनलाइन शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- सिडबी डिजिटल बैंकिंग सहायता कार्यक्रम के ऑनलाइन लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव एन.एन. सिन्हा ने भाग लिया।
- सखी मंडल की 4,620 महिलाएँ वर्तमान में लगभग 3,137 पंचायतों को बीसी सखियों के रूप में घर-घर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। लॉकडाउन के समय देश की इन बीसी सखियों ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए का लेन-देन किया और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाया।
- सिडबी द्वारा बीसी सखियों के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग की पहल को एक नया आयाम मिलेगा और जल्द ही सखी मंडल की दीदी बैंकिंग सखी हर पंचायत में संवाददाता के रूप में घर-घर सुविधा प्रदान कर सकेगी।
- सखी मंडल की बहनों को बीसी सखी के रूप में बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिये ग्रामीण विकास विभाग के तहत जेएसएलपीएस की पहल को सिडबी के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- सिडबी बीसी सखी पहल के लिये डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री, एमआईएस डैशबोर्ड और क्षमता निर्माण में अपनी सेवाएँ प्रदान करेगा।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने बांग्लादेश को भेजी सातवीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में दक्षिण-पूर्व रेलवे ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के राउरकेला से बांग्लादेश के बेनापोल के लिये 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन भेजी।

प्रमुख बिंदु

- यह ट्रेन राउरकेला से 10 कंटेनरों में 186 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) लेकर बांग्लादेश रवाना हुई।
- बांग्लादेश सरकार के अनुरोध पर कोविड प्रभावित रोगियों के इलाज के लिये तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की खेप भेजी जा रही है। बांग्लादेश के बेनापोल के लिये पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 24 जुलाई को टाटानगर से भेजी गयी थी।

नोट :

- अब तक चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत टाटानगर और राउरकेला से सात ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें बांग्लादेश भेजी जा चुकी हैं। टाटानगर से 200 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) बांग्लादेश को भेजी जा चुकी हैं।
- गौरतलब है कि कोविड प्रभावित रोगियों के इलाज़ के लिये ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये, दक्षिण-पूर्व रेलवे इस साल 23 अप्रैल से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है ताकि कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के इलाज़ के लिये आवश्यक तरल ऑक्सीजन की त्वरित परिवहन और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

गोड्डा में 60 योजनाओं का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 18 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा ज़िले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड के तेशोबथन गाँव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की 60 योजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया। साथ ही, विभिन्न विभागों द्वारा चुने गए कुछ लाभार्थियों को प्रधान पट्टा, नियुक्ति-पत्र और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 7,050.83 लाख रुपए की 37 योजनाओं का लोकार्पण एवं 2,230.42 लाख रुपए की 23 योजनाओं का शिलान्यास किया।
- उन्होंने आवास योजना के तहत छह हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी, जबकि चार हितग्राहियों को प्रधान पट्टा वितरित किया।
- इसके अलावा उन्होंने ज़िला स्थापना शाखा, मनरेगा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, आपूर्ति विभाग आदि द्वारा चयनित लाभार्थियों में से कुछ को सांकेतिक नियुक्ति-पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पट्टा, राशन कार्ड और पेंशन, अनुदान स्वीकृति-पत्र आदि प्रदान किये।
- मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया।

टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तीसरा फुट ओवरब्रिज

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में टाटानगर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण-पूर्व रेलवे (एसईआर) के मुख्यालय गार्डन रीच ने चक्रधरपुर रेलवे मंडल द्वारा भेजे गए तीसरे फुट ओवरब्रिज के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह तीसरा फुट ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन के खड़गपुर छोर पर बनेगा।

प्रमुख बिंदु

- अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन प्रबंधन ने कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें ओवरब्रिज भी शामिल है।
- टाटानगर रेलवे की इंजीनियरिंग विंग ने 2 करोड़ रुपए की परियोजना का अंतिम ब्लूप्रिंट पेश किया था, जिसे दक्षिण-पूर्व रेलवे ने मंज़ूरी दे दी है।
- योजना के तहत रेलवे स्टेशन के खड़गपुर छोर पर पहले फुट ओवरब्रिज के बगल में तीसरा फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 को अन्य चार प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। सितंबर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की उम्मीद है।
- स्टेशन प्रबंधन ने बताया कि प्लेटफॉर्मों पर खंभे लगाने के लिये जगह की पहचान कर ली गई है। परियोजना के लिये काम इस साल आरंभ में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण नहीं हो सका।
- गौरतलब है कि वर्तमान में ए1 श्रेणी के स्टेशन पर दो फुट ओवरब्रिज हैं। 1.90 करोड़ रुपए की लागत वाले दूसरे का उद्घाटन अक्टूबर 2019 में किया गया था।

नोट :

लाभार्थियों को नियुक्ति-पत्र व प्रमाण-पत्र का वितरण

चर्चा में क्यों ?

- 19 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज ज़िले के पटना प्रखंड स्थित धरमपुर गाँव में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लिये चयनित हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र एवं स्वीकृति-पत्र वितरित किये। वहीं तीन लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति-पत्र दिये गए।

प्रमुख बिंदु

- जिन योजनाओं के लिये हितग्राहियों का चयन किया गया है, उनमें पाँच मनरेगा, सात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, तीन डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास, 16 मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, नौ कन्यादान योजना, दो दिव्यांग यंत्र वितरण के लिये, 17 पेंशन स्वीकृति पत्र के लिये और छह ग्रीन राशन कार्ड के लिये हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सखी मंडलों को चेक प्रदान किये। इनमें सभी मंडलों को सर्कुलर फंड के तहत 7.80 लाख रुपए, सामुदायिक निवेश कोष के तहत 19 लाख रुपए और कैश क्रेडिट लिंकेज के तहत 28 लाख रुपए का चेक दिया गया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा स्थानीय लोगों की समस्याएँ सुनीं व संबंधित अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिये।

सौर ऊर्जा से संचालित होंगे राज्य के पाँच हवाई अड्डे

चर्चा में क्यों ?

- 26 अगस्त, 2021 को झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (जेआरईडीए) के निदेशक के.के. वर्मा ने बताया कि राँची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा और राज्य के चार अन्य आगामी हवाई अड्डे सरकार की हरित पहल के तहत सौर ऊर्जा से संचालित होंगे।

प्रमुख बिंदु

- हरित पहल के तहत राँची के अलावा, दुमका, देवघर, बोकारो और गिरिडीह के हवाई अड्डों को कवर किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिये 20 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं और इसे छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
- के.के. वर्मा ने कहा कि सौर पैनलों से लैस पाँच हवाई अड्डों में से प्रत्येक परियोजना पूरी होने के बाद हर दिन 600 किलोवाट बिजली का उत्पादन करेगी। यह पहल न केवल हवाई अड्डों को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि सौर ऊर्जा के साथ कुछ आवासीय क्षेत्रों को भी रोशन करेगी।
- बिरसा मुंडा हवाई अड्डा वर्तमान में झारखंड में एकमात्र पूर्ण-संचालित हवाई अड्डा है, शेष चार हवाई अड्डों में से कुछ का एक वर्ष के भीतर परिचालन शुरू होने की संभावना है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राँची हवाई अड्डे की विस्तार योजना को मंज़ूरी दे दी है और 300 एकड़ से अधिक क्षेत्र में हवाई अड्डे के विस्तार के लिये एएआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में पुदुचेरी हवाई अड्डा 2020 में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) के तहत पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बना था। इसके अलावा, यह दावा किया जाता है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (केरल), सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में चलने वाला दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है।

फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

- झारखंड में तिलाया, कोनार, मैथन और पंचेत (बंगाल-झारखंड) सहित दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC) से संबंधित सभी बाँधों में फ्लोटिंग सौर परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 50 मेगावाट होगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए इन सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है तथा DVC के सभी बाँधों पर फ्लोटिंग सौर परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी।
- DVC का उद्देश्य फ्लोटिंग सोलर और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। DVC की योजना वर्ष 2030 के अंत तक अपनी विद्युत् उत्पादन क्षमता को 10,000 मेगावाट तक बढ़ाना है।
- सक्रिय थर्मल इकाइयों के साथ-साथ निष्क्रिय थर्मल इकाइयों की अधिशेष भूमि पर भी सौर इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।
- लुगु हिल्स में एक 1500 मेगावाट पंप स्टोरेज प्लांट भी प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा जल्द ही बोकारो थर्मल प्लांट की बी प्लांट यूनिट में एक सौर ऊर्जा इकाई स्थापित कि जाएगी।

मेधा कृषि उत्सव

चर्चा में क्यों ?

- 30 अगस्त, 2021 को जन्माष्टमी के अवसर पर झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र, धुरवा, राँची में मेधा कृषि उत्सव (Medha Krishi Utsav) का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध संघ में दूध की आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को एक रुपए प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए बादल ने कहा कि झारखंड का दुग्ध व्यवसाय में उज्ज्वल भविष्य है और यह हमारे दुग्ध उत्पादकों के लिये एक सुनहरा अवसर है, इससे राज्य के लोगों को उनके अपने राज्य में आय का एक स्रोत मिलेगा।
- झारखंड राज्य दुग्ध संघ, जो मेधा ब्रॉन्ड के नाम से प्रसिद्ध है, पिछले छह वर्षों से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कुशल प्रबंधन में निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्तमान में राज्य के 18 ज़िलों के दुग्ध संघ से लगभग 40,000 दुग्ध उत्पादक परिवार जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन लगभग 1.30 लाख लीटर दूध की आपूर्ति कर रहे हैं।
- वर्तमान में दुग्ध संघ के तहत चार डेयरी संयंत्र (होटवार, कोडरमा, लातेहार और देवघर) 1.40 लाख लीटर की प्रसंस्करण क्षमता के साथ संचालित हैं, जबकि तीन नए संयंत्र, अर्थात् सरथ-देवघर, सहीगंज व पलामू निर्माण और उत्पादन के अंतिम चरण में हैं।
- इसके अलावा, दूध उत्पादकों की उत्पादन लागत को कम करने और दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से होटवार स्थित मेधा डेयरी परिसर में फेडरेशन द्वारा एक मवेशी चारा संयंत्र, खनिज मिक्सर प्लांट, बायपास फीड और कोल्ड ब्रीडिंग प्लांट भी स्थापित कर संचालित किया जा रहा है।
- इस अवसर पर कृषि मंत्री द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित उचित और सुलभ सलाह के लिये टेलीमेडिसिन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत पशुपालकों को विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों द्वारा उनके पशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में सलाह दी जाएगी।

नोट :